(ज) क्या इस सर्वेक्षण के अनुसार 1986 के मुकाबले जब यह मिशन शुरू हुआ था, 20,000 और ऐसे वास स्थल है जहां जल का कोई स्रोत नहीं है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभ ई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बिना सुरक्षित पेयजल वाली बसावटों के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां। लेकिन 1.4.92 को 2243 समस्याग्रस्त गांव थे।

(छ) बसावटों के सर्वेक्षण 1991–93 द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों का वैद्धीकरण पूरा नहीं किया गया है।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण सफाई योजना का कार्यान्वयन**

509. श्री राम लेउमनानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मई, 1994 के "डेली टैलीग्राफ" में "रूरल सेनीटेशन स्कीम ए फेलियर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन गत वर्षों के दौरान इन प्रयोजनों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993 94 के लिये क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वास्तव में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जा सके ;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी तथा उनके संबंध में रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी एक ही होने के कारण, संबंधित मुद्दों के आवश्यक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई विशेष तंत्र स्थापित करेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान कम लागत वाले

शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार रही है :–

| वर्ष | शौचालयों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत संयुक्त लक्ष्य | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त उपलब्धि | प्रतिशत उपलब्धि |
| 1991–92 | 341954 | 184957 | 54.08 |
| 1992–93 | 340915 | 328073 | 96.23 |
| 1993–94 | 499975 | 293701 | 57.74 |
| कुल : | 1182844 | 806731 | 68.20 |

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि राज्यों की स्वास्थ्य शिक्षा और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों की निगरानी के लिये स्वच्छता प्रकोष्ठ बनाने की सलाह दी गई है। केन्द्रीय स्तर पर भी निगरानी को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

**जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग**

510. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को हाल ही में यह चेतावनी दी गई है कि वे जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटित राशि का अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग न करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच भी है कि गत वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1992–93 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि जवाहर रोजगार योजना सहित अनेक योजनाएं अपेक्षित रूप में लाभकारी सिद्ध नहीं हुई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रभावी निगरानी व्यवस्था कायम करने पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) यह सच है कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधियों का अन्य प्रयोजनों पर इस्तेमाल न करें।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1992–93 की अपनी रिपोर्ट में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं किया है कि जवाहर